भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1045

08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

प्रौद्योगिकी विकास निधि

1045. श्री तापिर गाव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकी विकास निधि के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) उक्त निधि से क्या लाभ होने की संभावना है ; और

(ग) उक्त निधि की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना, एमओडी (रक्षा मंत्रालय) का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसे डीआरडीओ के द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है । प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

(i) रक्षा एवं दोहरी उपयोग प्रौद्योगिकियां जो कि वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के पास उपलब्ध नहीं हैं, के विकास हेतु शैक्षणिक व वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ-साथ एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स सहित, भारतीय उद्योगों को सहायता अनुदान प्रदान करना ।

(ii) सैन्य प्रौद्योगिकी के डिज़ाइन एवं विकास के संवर्धन हेतु निजी उद्योगों विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के साथ कार्य करना एवं सहायता अनुदान के साथ उनकी सहायता करना ।

(iii) उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियां, जिन्हें देश में प्रथम बार विकसित किया जा रहा है, के अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना ।

(iv) सशस्त्र बलों, अनुसंधान संगठनों, शैक्षणिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की अर्हक / प्रमाणीकरण करने वाली एजेंसियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ।

(v) अवधारणात्मक तथ्यों के साथ भविष्य की प्रौद्योगिकियों को बल प्रदान करना एवं उन्हें प्रोटोटाइप में बदलना ।

(ख) योजना के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ निम्नानुसार है :-

(i) देश में रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और डिजाइन हेतु भारतीय उद्योगों की क्षमता एवं सामर्थ्य का निर्माण करना ।

(ii) अनुसंधान एवं विकास के एक पारितंत्र का निर्माण करना जिसमें सशस्त्र बलों एवं रक्षा क्षेत्र की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योग तथा शैक्षिक जगत आपस में मिलकर कार्य करें ।

(iii) देश में रक्षा विनिर्माण पारितंत्र का निर्माण करना ।

(iv) रक्षा प्रौद्योगिकी में 'स्व-निर्भरता' और 'आत्मनिर्भरता' के लक्ष्य को प्राप्त करना ।

(ग) आज की तिथि तक, विभिन्न उद्योगों को कुल 291.25 करोड़ रुपए की लागत की कुल 70 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और योजना के तहत 16 रक्षा प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक विकसित / कार्यान्वित किया गया है ।

***